



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

P.O. — 250

KM — 30

CPB — 220

सं. 407]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 17, 2004/भाद्र 26, 1926

पूरा किया

No. 407]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 17, 2004/BHADRA 26, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2004

सं. 51/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

प्रभारी

रा० वि० एक

सा.का.नि. 618(अ).— केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1)

की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002-के.उ.शु. में और आगे संशोधन करती है:-

उक्त अधिसूचना में, -

(1) क्रम सं. 303 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् सारणी में निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

क्रम सं.	अध्याय शीर्ष अथवा उपशीर्ष	माल का वर्णन	पहली अनुसूची के तहत दर	दूसरी अनुसूची के तहत दर	शर्त सं.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
"304	43	सॉ, टेन्ड अथवा ड्रेस्ड फर स्किन	शून्य	—	—

[फा. सं. 605/40/2004-प्रतिअदायगी]

एच. के. प्रसाद, अवर सचिव

टिप्पणी :— अधिसूचना सं. 6/2002-के.उ.शु., तारीख 1 मार्च, 2002 को भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 127 (अ) के तहत तारीख 1 मार्च, 2002 को प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 50/2004-के.उ.शु., तारीख 16 सितम्बर, 2004 के तहत सा.का.नि. 615 (अ) तारीख 16 सितम्बर, 2004 के तहत प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2004

No. 51/2004-CENTRAL EXCISE

G.S.R. 618(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 6/2002-Central Excise, dated the 1st March, 2002, namely:-

In the said notification,-

(I) in the Table after S. No. 303 and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely,-

S. No.	Chapter or heading or sub-heading	Description of goods	Rate under the First Schedule	Rate under the Second Schedule	Condition No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"304.	43	Raw, tanned or dressed fur skins	Nil	-	-

[F.No. 605/40/2004-DBK]

H. K. PRASAD, Under Secy.

Note:— The notification No. 6/2002-Central Excise, dated the 1st March, 2002 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide G.S. R. 127 (E), dated the 1st March, 2002 and was last amended by notification No. 50/2004, dated the 16th September, 2004 published vide No. G.S.R. 615 (E), dated the 16th September, 2004.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2004

सं. 96/2004-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 619(अ).— केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एतद्वारा उस माल को छूट प्रदान करती है जिसका वर्णन नीचे सारणी के कॉलम (2) विनिर्दिष्ट है, जब भारत में इसका आयात किया जाए, -

- (क) सीमाशुल्क के उतने भाग से जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के तहत उद्ग्रहणीय है और जो उक्त सारणी के कॉलम (3) की सदृश्य प्रविष्टि में निर्दिष्ट दर से संगणित राशि से अधिक है ;

- (ख) सीमाशुल्क के उस भाग से जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के तहत उद्ग्रहणीय राशि से अधिक हो जिसकी संगणना उक्त सारणी के कालम (4) में दी गई तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर की गई है ;

निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, अर्थात् :-

- (i) यह कि आयातकर्ता को विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.3 अथवा पैराग्राफ 7.9 की शर्तों के अनुसरण में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा शुल्क हकदारी पास बुक जारी की गई हो ;
- (ii) आयातकर्ता को निर्यात किए गए उत्पादों के लिए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दरों पर अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा उक्त शुल्क हकदारी पास बुक में जमा प्रविष्टियां अनुज्ञात की गई है ;
- (iii) उक्त शुल्क हकदारी पास बुक माल पर उद्ग्रहणीय शुल्कों के विकलन के लिए सीमाशुल्क के समुचित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, जो यदि इसमें अंतर्विष्ट छूट न दी गई होती ;

बशर्त शुल्क से छूट उस दशा में अनुज्ञेय नहीं होगी जब माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क के विकलन के लिए उक्त शुल्क हकदारी पास बुक में अपर्याप्त जमा रकम हो यदि यह छूट न दी जाती;

- (iv) यह कि उक्त शुल्क हकदारी पास बुक उस रजिस्ट्री-करण पत्तन पर जो मुम्बई, कोलकाता, कोचीन, मगदल्ला, काकीनाड़ा, कांडला, मंगलौर, मारमागोवा, चैन्नई, नावाशेवा, पारादीप, पीपावव, सिक्का, तूतीकोरिन, विशाखापटनम, दाहेज, मुद्रा, नागापट्टिनम, ओखा, जामनगर और मुल्हारका स्थित समुद्री पत्तनों के माध्यम से अथवा अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, मुम्बई, कोलकाता, कोयम्बटूर, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, चैन्नई, श्रीनगर, त्रिवेन्द्रम, वाराणसी, नागपुर और कोचीन स्थित किसी भी विमानपत्तन के माध्यम से अथवा आगरा बंगलौर, कोयम्बटूर, दिल्ली, फरीदाबाद, गोवाहाटी, गुन्तूर, हैदराबाद, जयपुर, जालन्धर, कानपुर, लुधियाना, मुरादाबाद, नागपुर, पिम्परी (पुणे) पीतमपुर (इन्दौर), सूरत, तिरुपुर, वाराणसी, नासिक, रूद्रपुर (नैनीताल), दिघी (पुणे), बड़ोदरा, दौलताबाद (वंजारवाड़ी और मालीवाड़ा), वालुज (औरंगाबाद), अनापार्थी (आन्ध्र प्रदेश), सेलम, मालनपुर, सिंगनालुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अहमदाबाद, भिवाड़ी, मदुरई, मीलवाड़ा, पांडिचेरी, गड़ीहसारू, भटिण्डा, दम्पर (डेरा बासी), छेहराता (अमृतसर), करूर, मिराज, रिवाड़ी, भुसावल, जमशेदपुर, सूरजपुर और दादरी स्थित किसी अंतरदेशीय कंटेपर डिपो के माध्यम से या राणाघाट, सिंहबाद, रक्सौल, जोगबानी, नौतनवा (सौनोली), पैटरापोल और महादीपुर स्थित किसी भूमि सीमाशुल्क स्टेशन में से केवल आयात और निर्यात के लिए उक्त शुल्क हकदारी पास बुक के जारी किए जाने की तारीख से चौबीस मास के लिए या अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा स्वीकृत बढ़ी हुई अवधि के लिए वैध होगी ;

बशर्त कि जहां शुल्क हकदारी पास बुक की समाप्ति माह के अंतिम दिन से पूर्व समाप्त होती है, ऐसी शुल्क हकदारी पास बुक को उक्त माह के आखिरी दिन तक वैध माना जाएगा ;

बशर्त सीमाशुल्क आयुक्त विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उनके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं किसी अन्य समुद्री पत्तन, विमानपत्तन अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो या किसी भूमि सीमाशुल्क स्टेशन आयात और निर्यात अनुज्ञात कर सकेंगे ;

(v) जहां आयातकर्ता सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट का दावा नहीं करता है वहां यह समझा जाएगा कि उसने उक्त अतिरिक्त सीमाशुल्क की संगणना के प्रयोजन के लिए उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट शुल्क से छूट का उपभोग नहीं किया है ;

(vi) यह कि आयातक को प्रतिअदायगी अथवा उक्त शुल्क हकदारी पास बुक में डाली गई राशि के प्रति उक्त सीमाशुल्क टैरिफ की धारा 3 के तहत उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर का लाभ लेने का अधिकार होगा ;

(vii) जहां किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा शुल्क से छूट के लाभ का दावा किया जाता है, जिसके पास शुल्क हकदारी पास बुक नहीं है, वहां ऐसे लाभ केवल क्रेडिट राशि की विशिष्ट राशि के प्रति ही अनुमत्य होंगे, जो अनन्तिम क्रेडिट न होने के कारण, शुल्क हकदारी पास बुक धारक द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को अंतरित किए गए हों ;

2. यह अधिसूचना 31 मार्च, 2005 तक व जिसमें यह दिन भी शामिल है, तक प्रभावी रहेगी ।

सारणी

क्रम सं.	माल का वर्णन	मानक दर	अतिरिक्त शुल्क दर
1.	2.	3.	4.
1.	खाद्य तेलों को छोड़कर दूसरा माल	शून्य	शून्य
2.	खाद्य तेल	लागू शुल्क दर का 50 प्रतिशत	लागू अतिरिक्त शुल्क दर का 50 प्रतिशत

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ :-

- (i) “विदेश व्यापार नीति” से भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1/2004, तारीख 31 अगस्त, 2004 को प्रकाशित विदेश व्यापार नीति 2004-2009 से अभिप्रेत है ;
- (ii) “अनुज्ञापन प्राधिकारी” से विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के तहत नियुक्त किए गए महानिदेशक विदेश व्यापार अथवा उनके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है ;
- (iii) “लागू शुल्क दर” का अर्थ उस शुल्क की मानक दर से है, जो उक्त सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में उक्त सीमाशुल्क टैरिफ की पहली

अनुसूची में अन्य अधिसूचना के साथ पठित है (फिलहाल उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत ऐसे माल के संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार);

- (iv) “लागू अतिरिक्त शुल्क की दर” का अर्थ अन्य अधिसूचना के साथ पठित उक्त सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा (3) के तहत उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क से है (फिलहाल उक्त सीमाशुल्क की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत ऐसे माल के संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार) ।

[फा. सं. 605/40/2004-प्रतिअदायगी]

एच. के. प्रसाद, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2004

No. 96/2004-CUSTOMS

G.S.R. 619(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods of description specified in column (2) of the Table below, when imported into India, -

- (a) from so much of duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table;
- (b) from so much of additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table;

subject to the following conditions, namely :-

- (i) that the importer has been issued a Duty Entitlement Pass Book by the Licensing Authority in terms of paragraph 4.3 or paragraph 7.9 of the Foreign Trade Policy;
- (ii) that the importer has been permitted credit entries in the said Duty Entitlement Pass Book by the Licensing Authority at the rates notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry for the products exported;
- (iii) that the said Duty Entitlement Pass Book is produced before the proper officer of Customs for debit of the duties leviable on the goods, but for exemption contained herein :

Provided that exemption from duty shall not be admissible if there is insufficient credit in the said Duty Entitlement Pass Book for debiting the duty leviable on the goods, but for this exemption.

- (iv) the said Duty Entitlement Pass Book shall be valid for twenty four months from the date of issue or such extended period as may be granted by the Licensing Authority for import and export only, at the port of registration which shall be one of the sea ports at Mumbai, Kolkata, Cochin, Magdalla, Kakinada, Kandla Mangalore, Marmagao, Chennai, Nhava Sheva, Paradeep, Pipavav, Sikka, Tuticorin, Visakhapatnam, Dahej, Mundhra, Nagapattinam, Okha, Jamnagar and Muldwarka or through any of the airports at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Mumbai, Kolkata, Coimbatore, Delhi, Hyderabad, Jaipur, Chennai, Srinagar, Trivandrum, Varanasi, Nagpur and Cochin or through any of the Inland Container Depots at Agra, Bangalore, Coimbatore, Delhi, Faridabad, Gauhati, Guntur, Hyderabad, Jaipur, Jalandhar, Kanpur, Ludhiana, Moradabad, Nagpur, Pimpri (Pune), Pitampur (Indore), Surat, Tirupur, Varanasi, Nasik, Rudrapur (Nainital), Dighi

(Pune), Vadodara, Daulatabad (Wanjarwadi and Maliwada), Waluj (Aurangabad), Anaparthi (Andhra Pradesh), Salem, Malanpur, Singanalur, Jodhpur, Kota, Udaipur, Ahmedabad, Bhiwadi, Madurai, Bhilwara, Pondicherry, Garhi Harsaru, Bhatinda, Dappar (Dera Bassi), Chheharata (Amritsar), Karur, Miraj, Rewari, Bhusawal, Jamshedpur, Surajpur and Dadri or through the Land Customs Station at Ranaghat, Singhabad, Raxaul, Jogbani, Nautarva (Sonauli), Petrapole and Mahadipur:

Provided that where the expiry of the Duty Entitlement Pass Book falls before the last day of the month, such Duty Entitlement Pass Book shall be deemed to be valid till the last day of the said month:

Provided further that the Commissioner of Customs may, by special order and subject to such conditions as may be specified by him, permit imports and exports from any other sea port, airport, inland container depot or through any land customs station;

- (v) that where the importer does not claim exemption from the additional duty of customs leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), he shall be deemed not to have availed the exemption from the duty specified in the First Schedule to the said Customs Tariff Act for the purpose of calculation of the said additional duty of customs;
 - (vi) that the importer shall be entitled to avail the drawback or CENVAT credit of additional duty leviable under section 3 of the said Customs Tariff Act against the amount debited in the said Duty Entitlement Pass Book;
 - (vii) that where benefit of exemption from duty is claimed by a person, who is not a Duty Entitlement Pass Book holder, such benefit shall be permissible only against specific amount of credit, not being a provisional credit, transferred by a Duty Entitlement Pass Book holder to such person.
2. This notification shall have effect upto and inclusive of the 31st day of March, 2005.

TABLE

S.No.	Description of goods	Standard rate	Additional duty rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Goods other than edible oils	Nil	Nil
2.	Edible oils	50% of applied rate of duty	50% of applied rate of additional duty

Explanation, - For the purposes of this notification, -

- (i) "Foreign Trade Policy" means Foreign Trade Policy 2004-2009 published in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry vide No. 1/2004, dated the 31st August, 2004;
- (ii) "Licensing Authority" means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorized by him to grant a licence under the said Act;
- (iii) "applied rate of duty" means the standard rate of duty specified in the First Schedule to the said Customs Tariff Act with respect to the goods specified in column (2) of the said Table, read with any other notification (for the time being in force) issued in respect of such goods under sub-section (1) of section 25 of the said Customs Act;

(iv) "applied rate of additional duty" means the additional duty leviable under section 3 of the said Customs Tariff Act with respect to the goods specified in column (2) of said Table, read with any other notification (for the time being in force) issued in respect of such goods under sub-section (1) of section 25 of the said Customs Act.

[F.No. 605/40/2004-DBK]

H. K. PRASAD, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2004

सं. 97/2004-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 620(अ).— केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, इससे उपाबद्ध सारणी में विनिर्दिष्ट माल को, -

(i) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय उतनी सीमाशुल्क से, जो मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है; और

(ii) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3' के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क से छूट देती है, जब आयातक द्वारा विशेष रूप से दावा किया गया हो।

2. इस अधिसूचना के तहत छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होगी, अर्थात् :-

(1) यह कि आयातित माल, विदेश व्यापार नीति के अध्याय 5 के निबंधनों के अनुसार निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम के अधीन जारी की गई किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आता है, जिसके द्वारा 5 प्रतिशत शुल्क की दर से माल का आयात अनुज्ञात किया गया है और उक्त अनुज्ञप्ति निकासी के समय उचित सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा विकलन के लिए प्रस्तुत की जानी है;

परन्तु उक्त सारणी की क्रम संख्या 4 में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त पुर्जों के आयात के लिए अनुज्ञप्ति की विधिमान्य अवधि वह अवधि मानी जाएगी जो संपूर्ण निर्यात बाध्यता को पूरा करने के लिए अनुज्ञात की गई हो।

(2) यह कि आयातकर्ता से ऐसे प्रारूप में और ऐसी राशि के लिए ऐसे प्रतिभू या प्रतिभूति सहित जो सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, पोत पर्यन्त निःशुल्क आधार पर आयातित माल पर बचाए गए शुल्क के आठ गुणे के बराबर, जैसा कि अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट है या ऐसी उच्चतर राशि के लिए, जो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा नियत की जाए, निम्नलिखित अनुपात में अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने की तारीख से आठ वर्ष की अवधि के भीतर, स्वयं को निर्यात बाध्यता पूर्ण करने में आबद्ध करते हुए एक बंधपत्र निष्पादित करता है, अर्थात् :-

क्रम सं.	अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने की तारीख से अवधि	कुल निर्यात बाध्यता का अनुपात
1.	2.	3.
1.	पहले से छठे वर्ष का ब्लॉक	50 प्रतिशत
2.	सात से आठ वर्ष का ब्लॉक	50 प्रतिशत

परन्तु जहां बचाया गया शुल्क 100 करोड़ रुपये से कम न हो अथवा जहां कृषि निर्यात जोन में इकाइयों को लाइसेंस जारी किया जाता है, जैसा कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाता है, वहां निर्यात बाध्यता लाइसेंस जारी किए जाने की तारीख से 12 वर्षों की अवधि के भीतर निम्न अनुपातों में पूरी की जाएगी, अर्थात् :-

क्रम सं.	अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने की तारीख से अवधि	कुल निर्यात बाध्यता का अनुपात
1.	2.	3.
1.	एक से 10 वर्ष का ब्लॉक	50 प्रतिशत
2.	11 और 12 वर्ष का ब्लॉक	50 प्रतिशत

परन्तु यह कि जहां कोई रुग्ण इकाई औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा अधिसूचित है अथवा जहां रुग्ण इकाई के संबंध में इसके पुनर्जीवन के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा कोई पुनर्वास स्कीम घोषित की जाती है, वहां निर्यात बाध्यता विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 5.5.1 की शर्तों के अनुसार पूरी की जाएगी ;

बशर्ते कि जहां पूंजीगत माल प्रौद्योगिकी उन्नति के लिए आयात किया जाता है, वहां पर निर्यात बाध्यता आयातित माल पर बचाए गए शुल्क के छह गुने के बराबर जैसा कि अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट है, निश्चित की जाएगी, या ऐसी उच्चतर राशि के लिए जो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने की तारीख से आठ वर्ष के भीतर निश्चित की जाएगी ;

परन्तु किसी विशिष्ट ब्लॉक वर्ष की निर्यात बाध्यता को पूर्ववर्ती ब्लॉक में किए गए अधिक निर्यातों द्वारा मंजूर किया जा सकेगा ;

(3) यह कि यदि आयातकर्ता सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क के संबंध में छूट का दावा नहीं करता है, तो उसे निर्यात बाध्यता के परिगणन के संबंध में बचाई गई शुल्क राशि के संगणन के प्रयोजनार्थ उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट शुल्क से छूट प्राप्त करने संबंधी लाभ उठाने वाला नहीं समझा जाएगा ;

(4) यह कि आयातकर्ता, अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने की तारीख से प्रत्येक ब्लॉक की समाप्ति से तीस दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क आयुक्त अनुज्ञात करें, सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क आयुक्त को समाधानप्रद रूप में पूरी की गई निर्यात बाध्यता का परिणाम दर्शित करने से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करता है और जहां किसी विशिष्ट ब्लॉक की निर्यात बाध्यता पूर्ववर्ती शर्त के निबंधनों के अनुसार

पूरी नहीं की गई है, वहां आयातकर्ता, उक्त ब्लॉक की समाप्ति से तीन मास के भीतर उतनी रकम का, जो यदि इसमें अंतर्विष्ट छूट न दी गई होती तो, माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क के उस भाग के बराबर का जिसका वही अनुपात है जो निर्यात बाध्यता को पूरा न किए गए भाग का कुल निर्यात बाध्यता से है, माल की निकासी की तारीख से 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर सहित संदाय करेगा ;

(5) यह कि आयातित, समंजित या विनिर्मित पूंजी माल आयातकर्ता के कारखाने या परिसर में संस्थापित किए जाते हैं और अधिकारिता वाले यथा-स्थिति सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या उप उत्पाद शुल्क आयुक्त से आयातकर्ता के कारखाने या परिसरों में पूंजी माल के संस्थापन और उपयोग की पुष्टि करने वाला एक प्रमाण-पत्र आयात के पूरा होने की तारीख से छह मास के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो उक्त सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क आयुक्त अनुज्ञात करे, यथास्थिति प्रस्तुत किया जाता है :

बशर्ते कि यदि आयातक सेवा प्रदान करने वाला है, तो वह संस्थापन का उक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकता है और स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा बताए गए प्रयोग को बता सकता है ;

बशर्ते कि आगे निम्नलिखित के संबंध में, -

- (i) ऐसा विनिर्माता निर्यातकर्ता और वणिक निर्यातकर्ता जिसका समर्थक विनिर्माता/विक्रेता हो ;
- (ii) कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए संविदा कृषि में उपयोग के लिए सिंचाई उपकरणों का आयात ; और
- (iii) इम्पोर्टर रेंडरिंग सर्विसेज़,

पूंजीगत माल, किसी ऐसे अन्य व्यक्ति(यों) के कारखाने में या परिसर में संस्थापित किया जा सकेगा जिसका नाम और पता शर्त (1) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित किया गया है और जहां आयातकर्ता और ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा शुल्क के पूर्ण अंतर के लिए बंधपत्र, शर्त (2) के निबंधनानुसार जहां-कहीं आवश्यक है, बैंक प्रत्याभूति सहित निष्पादित किया गया है और ऐसे विनिर्माता या अन्य व्यक्ति निर्यात बाध्यता को और इस अधिसूचना की अन्य सभी शर्तों को पूरा करने के लिए और व्यतिक्रम की दशा में 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित शुल्क का संदाय करने के लिए स्वयं को संयुक्त रूप से एवं पृथक रूप से आबद्ध करते हैं ;

बशर्ते की कृषि निर्यात जोन में स्थित एग्रो इकाईयों के लिए सेवा प्रदान करने वाला क्षेत्राधिकारिक उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा सहायक उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को सूचित करते हुए कृषि निर्यात जोन के अंदर पूंजीगत माल को ले जा सकता है, यथास्थिति इस शर्त के अधीन कि ऐसी गतिविधियों का आयातक सही रिकार्ड रखेगा ;

(6) यह कि आयात और निर्यात मुम्बई, कोलकाता, कोचीन, मगदल्ला, काकीनाड़ा, कांडला, मंगलौर, मारमागोवा, चैन्नई, नावाशेवा, पारादीप, पीपावद, सिक्का, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, दाहेज, मुद्रा, नागापट्टिनम, ओखा, जामनगर और मुल्द्वारका स्थित समुद्री पत्तनों के माध्यम से

अथवा अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, मुम्बई, कोलकाता, कोयम्बटूर, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, चैन्नई, श्रीनगर, त्रिवेन्द्रम, वाराणसी, नागपुर और कोचीन स्थित किसी भी विमानपत्तन के माध्यम से अथवा आगरा बंगलौर, कोयम्बटूर, दिल्ली, फरीदाबाद, गोवाहाटी, गुन्टूर, हैदराबाद, जयपुर, जालन्धर, कानपुर, लुधियाना, मुरादाबाद, नागपुर, पिम्परी (पुणे) पीतमपुर (इन्दौर), सूरत, तिरुपुर, वाराणसी, नासिक, रूद्रपुर (नैनीताल), दिघी (पुणे), बड़ोदरा, दौलताबाद (वंजारवाड़ी और मालीवाड़ा), वालुज (औरंगाबाद), अनापार्थी (आन्ध्र प्रदेश), सेलम, मालनपुर, सिंगनालुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अहमदाबाद, भिवाड़ी, मदुरई, भीलवाड़ा, पांडिचेरी, गड़ीहसारू, भटिण्डा, दप्पर (डेरा बासी), छेहराता (अमृतसर), करूर, मिराज, रिवाड़ी, भुसावल, जमशेदपुर, सूरजपुर और दादरी स्थित किसी अंतरदेशीय कंटेपर डिपो के माध्यम से या राणाघाट, सिंहबाद, रक्सौल, जोगबानी, नौतनवा (सौनोली), पैटरापोल और महादीपुर स्थित भूमि सीमाशुल्क स्टेशन के माध्यम से किया जाता है।

(7) शर्त (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी, निर्यात बाध्यता का पूरा करने करने वाली अवधि अथवा किसी ब्लॉक(कों) को बढ़ाया जाना मंजूर करता है या ऐसी निर्यात बाध्यता में 2 वर्ष तक की अवधि में पांच प्रतिशत से अनधिक की कमी को नियमित करता है वहां निर्यात बाध्यता को पूरा करने की उक्त अवधि को बढ़ाया जा सकेगा और यथास्थिति सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा माफ की गई निर्यात बाध्यता की उक्त कमी मंजूर की जा सकेगी :

परन्तु शर्त (2) के दूसरे उपबंध में विनिर्दिष्ट रुग्ण इकाइयों के संबंध में, समग्र रूप से निर्यात बाध्यता अवधि में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी।

3. जहां उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट माल दोषपूर्ण या उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, वहां उक्त माल का उसे आयात किए जाने पर शुल्क के संदाय की तारीख से 3 वर्ष के भीतर विदेशी प्रदायकर्ता को वापिस पुनःनिर्यात किया जा सकेगा :

परन्तु यह कि निर्यात के समय यथास्थिति सहायक आयुक्त या उप सीमाशुल्क आयुक्त के समाधानप्रद रूप में यह पहचान कर ली जाती है कि यह वही माल है जिसका कि आयात किया गया था।

सारणी

क्रम सं.	माल का वर्णन
1.	2.
1.	उत्पादन पूर्व, उत्पाद और उत्पाद के पश्चात् के लिए पूंजीगत वस्तुएं जिनमें 10 साल तक के पुराने पूंजीगत माल शामिल हैं।
2.	एसकेडी/सीकेडी दशा में पूंजीगत वस्तुएं जिन्हें आयातक द्वारा पूंजीगत वस्तुओं में संयोजित किया जाता है।
3.	आयातक द्वारा संयोजन अथवा पूंजीगत वस्तुओं के लिए अपेक्षित पूंजीगत वस्तुओं के संघटक।
4.	क्रम सं. 1, 2, और 3 में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के फालतू पुर्जे जैसा कि यथा आयातित, संयोजित अथवा विनिर्मित पूंजीगत वस्तुओं के अनुस्क्षण के लिए अपेक्षित हैं और जिनका

	वास्तविक रूप से आयात किया गया है।
5.	लाइसेंस धारक के मौजूदा संयंत्र और मशीनरी के लिए फालतू पुर्जे सहित उपभोज्य।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ :-

(1) “पूंजीगत माल” से तात्पर्य वही है जैसा कि इसे निर्यात और आयात नीति के पैराग्राफ 9.12 में दिया गया है ;

(2) “निर्यात और आयात नीति” से भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1/2004, तारीख 31 अगस्त, 2004 द्वारा समय-समय पर यथा-प्रकाशित निर्यात और आयात नीति 2004-2009 से अभिप्रेत है ;

(3) “अनुज्ञापन प्राधिकारी” से विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के तहत नियुक्त किए गए महानिदेशक विदेश व्यापार अथवा उनके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है ;

(4) “निर्यात बाध्यता” से, -

(i) ऐसे आयातकर्ता के संबंध में, उनसे भिन्न जो सेवाएं दे रहें हैं, ऐसा निर्यात अभिप्रेत है जो इस अधिसूचना के निबंधनों के अनुसार, आयातित, समंजित या विनिर्मित पूंजीगत माल का उपयोग करके विनिर्मित उत्पादों का भारत के बाहर किसी स्थान को निर्यात करते हैं :

परन्तु कि निर्यात बाध्यता निम्नोक्त द्वारा भी पूरी की जाए :-

(क) इसी उत्पाद का निर्यात करना जिसका उत्पाद उक्त पूंजीगत माल का प्रयोग करके ही किया जा सके ; अथवा

(ख) इसी उत्पाद का निर्यात करना जो लाइसेंस धारक के भिन्न-भिन्न एककों में तैयार किया गया हो ; अथवा

(ग) किसी निर्यातक द्वारा किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से किए गए निर्यातों अथवा लाइसेंसधारक की ओर से किसी उत्पादनकर्ता द्वारा किए गए इसी उत्पाद के निर्यात संबंधी मामलों में, अन्य बातों के साथ-साथ लदान बिलों में तीसरे पक्ष तथा लाइसेंसधारक के नामों का उल्लेख भी किया जाना चाहिए ; और

(घ) विदेश व्यापार नीति के पैरा 54 की शर्तों के अनुसार विनिर्मित उत्पाद की आपूर्ति करना ; और

(ड.) आयातक द्वारा निर्मित अन्य माल का निर्यात ;

(ii) सेवाएं देने वाले आयातकर्ताओं के संबंध में ऐसी पूंजी मालों का उपयोग करके दी गई सेवाओं के लिए मुक्त रूप से संपरिवर्तनीय विदेशी करेंसी में संदायों को प्राप्त करना अभिप्रेत है;

परंतु यह कि निर्माता निर्यातक और सेवा देने वाले के रूप में लाइसेंस धारक इकाइयों के संबंध में, निर्यात बाध्यता या तो उप-खंड (i) में निर्दिष्ट उत्पादों के निर्यात द्वारा अथवा ऐसी पूंजीगत वस्तुओं के प्रयोग के माध्यम से दी गई सेवाओं के लिए मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी करेंसी में अदायगियां प्राप्त करके पूरी की जाएगी ।

बशर्ते विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 9.28 में यथा-परिभाषित समूह कम्पनी के संबंध में, जहां पर ऐसी समूह कम्पनियों में से किसी एक को लाइसेंस जारी कर दिया जाता है, वहां पर निर्यात बाध्यता ऐसी समूह कम्पनी के अंतर्गत आने वाली किसी अन्य कम्पनी के द्वारा विनिर्मित माल के निर्यात द्वारा भी पूरी की जा सकती है ;

बशर्ते पोर्ट हैंडलिंग सैक्टर में सेवा प्रदान करने वाले के संबंध में, निर्यात बाध्यता भारतीय रूपयों में सर्विस प्रभागों के रूप में पूरी की जा सकती है जोकि अन्यथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुक्त विदेशी विनिमय के रूप में मानी जाएगी :

बशर्ते कि होटलों के संबंध में निर्यात बाध्यता विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 9.36 में यथा परिभाषित प्रबंधक होटलों के द्वारा पूरी की जाएगी ।

[फा. सं. 605/40/2004-प्रतिअदायगी]

एच. के. प्रसाद, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2004

No. 97/2004-CUSTOMS

G.S.R. 620(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods specified in the Table annexed hereto, from,—

(i) so much of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) as is in excess of the amount calculated at the rate of five per cent ad-valorem, and

(ii) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, when specifically claimed by the importer.

2. The exemption under this notification shall be subject to the following conditions, namely :—

(1) that the goods imported are covered by a valid licence issued under the Export Promotion Capital Goods Scheme in terms of Chapter 5 of the Foreign Trade Policy permitting import of goods at the rate of five percent duty and the said licence is produced for debit by the proper officer of customs at the time of clearance:

Provided that for import of spare parts specified at S.No.4 of the said Table, the validity period of the licence shall be deemed to be the period permitted for fulfillment of the export obligation in full;

(2) that the importer executes a bond in such form and for such sum and with such surety or security as may be specified by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs binding himself to fulfil export obligation on FOB basis equivalent to eight times the duty saved on the goods imported as may be specified on the licence, or for such higher sum as may be fixed by the Licensing Authority, within a period of eight years from the date of issue of licence, in the following proportions, namely :-

S.No.	Period from the date of issue of licence	Proportion of total export obligation
(1)	(2)	(3)
1.	Block of 1 st to 6 th year	50%
2.	Block of 7 th to 8 th year	50%

Provided that where the duty saved is not less than Rs.100 crores, or where the licence is issued to units in the agri export zone as may be notified by the licensing authority, the export obligation shall be fulfilled within a period of twelve years from the date of issue of licence in the following proportions, namely :-

S.No.	Period from the date of licence	Proportion of total export obligation
(1)	(2)	(3)
1.	Block of 1 st to 10 th year	50%
2.	Block of 11 th and 12 th year	50%

Provided further that where a sick unit is notified by the Board for Industrial and Financial Reconstruction or where a rehabilitation scheme is announced by the concerned State Government in respect of sick unit for its revival, the export obligation may be fulfilled in terms of Paragraph 5.5.1 of the Foreign Trade Policy:

Provided also that where the capital goods are imported for technological upgradation, the export obligation shall be fixed equivalent to six times the duty saved on the goods imported as may be specified on the licence, or for such higher sum as may be fixed by the Licensing Authority, within a period of eight years from the date of issue of licence;

Provided also that export obligation of a particular block may be set off against the excess exports made in the said preceding block;

(3) that if the importer does not claim exemption from the additional duty leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), he shall be deemed not to have availed of the exemption from the duty specified in the First Schedule to the said Customs Tariff Act for the purpose of calculation of the duty saved amount for calculation of export obligation;

(4) that the importer produces within 30 days from the expiry of each block from the date of issue of licence or within such extended period as the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs may allow, evidence to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs showing the extent of export obligation fulfilled, and where the export obligation of any particular block is not fulfilled in terms of the preceding condition, the importer shall within three months from the expiry of the said block pay duties of customs of an equal amount equal

to that portion of duties leviable on the goods, but for the exemption contained herein which bears the same proportion as the unfulfilled portion of the export obligation bears to the total export obligation together with interest at the rate of 15 per cent per annum from the date of clearance of the goods;

(5) that the capital goods imported, assembled or manufactured are installed in the importer's factory or premises and a certificate from the jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise or Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, is produced confirming installation and use of capital goods in the importer's factory or premises, within six months from the date of completion of imports or within such extended period as the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, may allow :

Provided that if the importer is a service provider, he may produce said certificate of installation and usage issued by an independent chartered engineer:

Provided further that in the case of, -

- (i) manufacturer exporter and merchant exporter having supporting manufacturer(s) or vendor(s);
- (ii) import of irrigation equipment for use in contract farming for export of agricultural products; and
- (iii) importer rendering services,

the capital goods may be installed at the factory or premises of such other person whose name and address are endorsed on the licence referred to in condition (1) and where the bond for full difference of duty, if necessary, in terms of condition (2), with or without a bank guarantee, as the case may be, is executed by the importer and such other person binding themselves jointly and severally to fulfil the export obligation and all other conditions of this notification and to pay duty with interest at the rate of 15 per cent per annum in case of default;

Provided also that agro units located in Agri Export Zones or service providers in Agri export Zones may move the capital goods within the Agri Export Zones under intimation to the jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise or Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, subject to the condition that the importer shall maintain accurate record of such movement.

(6) that the imports and exports undertaken through seaports at Mumbai, Kolkata, Cochin, Magdalla, Kakinada, Kandla Mangalore, Mormagoa, Chennai, Nhava Sheva, Paradeep, Pipavav, Sikka, Tuticorin, Visakhapatnam, Dahej, Mundhra, Nagapattinam, Okha, Jamnagar and Muldwarka or through any of the airports at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Mumbai, Kolkata, Coimbatore, Delhi, Hyderabad, Jaipur, Chennai, Srinagar, Trivandrum, Varanasi, Nagpur and Cochin or through any of the Inland Container Depots at Agra, Bangalore, Coimbatore, Delhi, Faridabad, Gauhati, Guntur, Hyderabad, Jaipur, Jalandhar, Kanpur, Ludhiana, Moradabad, Nagpur, Pimpri (Pune), Pitampur (Indore), Surat, Tirupur, Varanasi, Nasik, Rudrapur (Nainital), Dighi (Pune), Vadodara, Daulatabad (Wanjarwadi and Maliwada), Waluj (Aurangabad), Anaparthi (Andhra Pradesh), Salem, Malanpur, Singaialur, Jodhpur, Kota, Udaipur, Ahmedabad, Bhiwadi, Madurai, Bhilwara, Pondicherry, Garhi Harsaru, Bhatinda, Dappar (Dera Bassi), Chheharata (Amritsar), Karur, Miraj, Rewari, Bhusawal, Jamshedpur, Surajpur and Dadri or through the Land Customs Station at Ranaghat, Singhabad, Raxaul, Jogbani, Nautanva (Sonauli), Petrapole and Mahadipur.

(7) notwithstanding anything contained in condition (4), where the Licensing Authority grants extension of block-wise period for any block(s) or overall period of fulfilment of export obligation upto a period of two years or regularization of shortfall in export obligation, not exceeding five per cent of such export obligation, the said block-wise period or overall period of export obligation shall be extended or condoned by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be :

Provided that in respect of sick unit referred to in the second proviso to condition (2), extension of overall period of export obligation shall not be allowed.

3. Where the goods specified in the said Table are found defective or unfit for use, the said goods may be re-exported back to the foreign supplier within 3 years from the date of payment of duty on the importation thereof:

Provided that at the time of re-export, the goods are identified to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, as the goods which were imported.

TABLE

S.No.	Description of goods
(1)	(2)
1.	Capital goods for pre-production, production and post production including second hand capital goods.
2.	Capital goods in SKD/CKD conditions to be assembled into capital goods by the importer.
3.	Components of capital goods required for assembly or manufacture of capital goods by the importer.
4.	Spare parts of goods specified at Serial Nos.1,2 and 3 as actually imported and required for maintenance of capital goods so imported, assembled, or manufactured.
5.	Spare parts including consumables for the existing plant and machinery of the licence holder.

Explanation – For the purposes of this notification,-

(1) “Capital goods” has the same meaning as assigned to it in Paragraph of 9.12 of the Foreign Trade Policy;

(2) “Foreign Trade Policy” means the Foreign Trade Policy 2004-2009 published vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, No. 1/2004 dated the 31st August, 2004 as amended from time to time;

(3) “Licensing Authority” means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorized by him to grant a licence under the said Act;

(4) “export obligation”, -

(i) in relation to importers other than those rendering services, means exports to a place outside India, of products manufactured with the use of capital goods imported, assembled or manufactured in terms of this notification :

Provided that export obligation may also be fulfilled by,-

- export of same products capable of being manufactured with the use of said capital goods; or
- export of same products manufactured in different units of the licence holder; or
- through third party exports made by an exporter or manufacturer on behalf of the licence holder by exporting the same product and in such cases, *inter-alia* the shipping bills shall indicate name of both the third party and the licence holder; or
- making supplies of manufactured product in terms of paragraph 5.4 of the Foreign Trade Policy; or
- export of other goods manufactured by the importer;

(ii) in relation to importers rendering services, means, receiving payments in freely convertible foreign currency for services rendered through the use of capital goods :

Provided that in respect of units holding licence both as manufacturer exporter and service provider, the export obligation may be fulfilled either by export of products specified in sub-clause (i) or by receiving payments in freely convertible foreign currency for services rendered through the use of such capital goods.

Provided further that in respect of Group Company as defined in paragraph 9.28 of the Foreign Trade policy where licence has been issued to any one of such Group Company, the export obligation may also be fulfilled by export of manufactured goods by any other company(s) belonging to such Group Company:

Provided also that in respect of service providers in the Port Handling sector, the export obligation may be fulfilled by earning service charges in Indian rupees which are otherwise considered as free foreign exchange by the Reserve Bank of India:

Provided also that in respect for hotels the export obligation may also be fulfilled by Managed Hotels as defined in paragraph 9.36 of the Foreign Trade Policy.

[F.No. 605/40/2004-DBK]

H. K. PRASAD, Under Secy.